NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
जून 2025, नई दिल्ली

पैक्स का कारोबारी विस्तार

बढ़ रहा ग्रामीण रोजगार

अंदर के पन्नों पर

- डेयरी क्षेत्र में बनेंगी तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी
- एनसीसीएफ के प्रयासों से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को हो रहा फायदा

nbt.india
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
my GOV मेरी सरकार

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा
प्रधानमंत्री-युवा 2.0
पुस्तकमाला के अंतर्गत प्रकाशित हिंदी की पुस्तकें

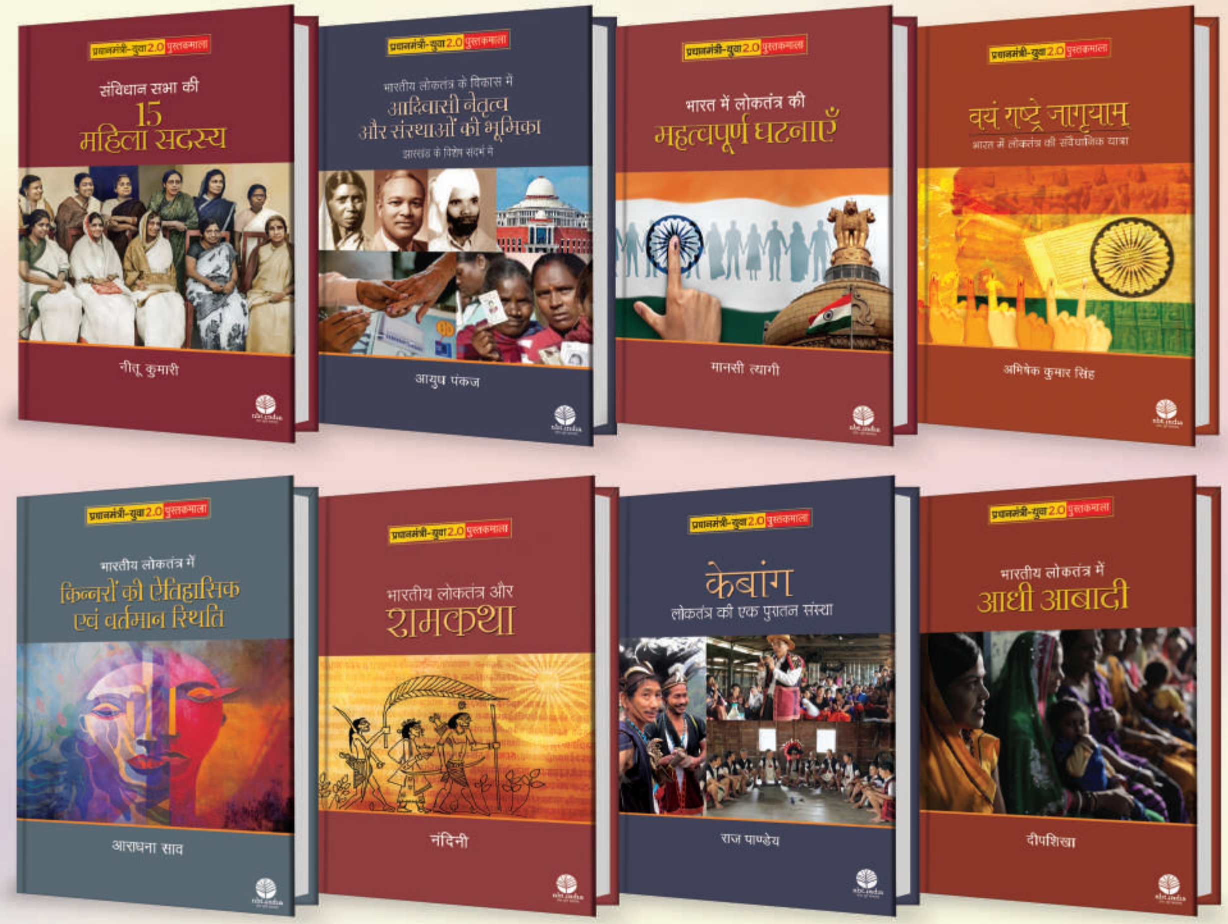

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा
वर्ष 2025–26 में आयोजित किए जाने वाले पुस्तक मेले

चिनार पुस्तक महोत्सव, जम्मू कश्मीर
2 से 10 अगस्त 2025

गोमती पुस्तक महोत्सव, लखनऊ
20 से 28 सितंबर 2025

मुंबई पुस्तक मेला, महाराष्ट्र
8 से 12 अक्तूबर 2025

गोरखपुर पुस्तक महोत्सव, उत्तर प्रदेश
1 से 9 नवंबर 2025

नागपुर पुस्तक मेला, महाराष्ट्र
22 से 30 नवंबर 2025

पुणे पुस्तक महोत्सव, महाराष्ट्र
13 से 21 दिसंबर 2025

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला
10 से 18 जनवरी 2026

संबलपुर पुस्तक मेला, ओडिशा
24 जनवरी से 1 फरवरी 2026

मुख्यालय
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
वेबसाइट: www.nbtindia.gov.in

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-12, जून-2025

निदेशक मंडल एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जीएम ऑफसेट, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमारः पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

पैक्स बने ग्रामीण रोजगार के वाहक 04
त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का गवर्निंग बोर्ड गठित 05

06 पैक्स का कारोबारी विस्तार बढ़ रहा ग्रामीण रोजगार

18 सहकारिता से संवरेगा युवाओं का भविष्य

सहकारिता से सशक्त हो रहे बिहार के बागवान 15
नीली क्रांति से युवाओं को मिल रहे अवसर 20
युवाओं में बढ़ रही वित्तीय जागरूकता 23
उत्तराखंड में बनेंगे 1000 स्टार्टअप 24
शुभमन के बहुत काम आएंगे अनुभवी खिलाड़ी 26
रेपो रेट में कमी से इकोनॉमी को बूस्टर डोज 28
एनवाईसीएस की मदद से बने आत्मनिर्भर 30

पैक्स बने ग्रामीण रोजगार के वाहक

सरकार की इन पहलों से पैक्स ग्रामीण रोजगार पैदा करने के बड़े वाहक के रूप में उभर रहे हैं। सशक्त एवं सक्षम गांव, विकसित भारत के निर्माण और भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में इनकी भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है।

सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह तभी संभव है जब गांवों में कारोबारी दायरा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस मूल बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही सहकारिता की प्राथमिक इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को सशक्त बनाने की पहल शुरू कर दी थी। पैक्स को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहले पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया जिसके तहत सभी सक्रिय पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने और चुनाव प्रक्रिया को भाई-भतीजावाद से मुक्त करने का फैसला किया गया। इसके बाद इसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की पहल की गई जिसके तहत पैक्स को करीब दो दर्जन व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की मंजूरी दी गई। इन फैसलों को कानूनी रूप देने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज में बदलाव किया गया जो पूरे देश में लागू हो चुका है। पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी दिया गया है।

पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) चलाने, जन औषधि और किसान समृद्धि केंद्र खोलने, उचित मूल्य की राशन दुकानें और अनाज खरीद केंद्र खोलने, पेट्रोल पंप और एलपीजी वितरण केंद्र खोलने, बीमा एवं बैंक मित्र, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने और उनका संचालन करने जैसी गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सीएससी खोलने में पैक्स सबसे आगे रहे हैं। देश में वर्तमान में करीब 1.05 लाख पुराने पैक्स हैं जिनमें से करीब 70 हजार सक्रिय हैं। सक्रिय पैक्स में से करीब 44 हजार पैक्स सीएससी के रूप में काम करने लगे हैं। इसी तरह, 36 हजार से ज्यादा पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में अपग्रेड हो गए हैं। 22 हजार से ज्यादा पैक्स उचित मूल्य की राशन दुकानों और 19 हजार से ज्यादा पैक्स अनाज खरीद केंद्र के रूप में काम करने लगे हैं। इनके अलावा, करीब तीन हजार पैक्स जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की तैयारी में जुटे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से लाखों स्थानीय ग्रामीणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पैक्स में गोदामों के निर्माण, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि क्षेत्र की बुनियादी अवसंरचना विकसित करने का कार्यक्रम जोरशोर से चल रहा है। यह भी ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। इसके अलावा, देशभर में दो लाख नए पैक्स बनाने की योजना के तहत 19 हजार से ज्यादा मल्टी परपज पैक्स (एमपैक्स), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। इनके माध्यम से भी ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। सरकार ने अब निष्क्रिय पैक्स में भी जान फूंकने के लिए कमर कस ली है और इसके लिए नई योजना लाने की तैयारी चल रही है।

सरकार की इन पहलों से पैक्स ग्रामीण रोजगार पैदा करने के बड़े वाहक के रूप में उभर रहे हैं। सशक्त एवं सक्षम गांव, विकसित भारत के निर्माण और भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में इनकी भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है। ■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का गवर्निंग बोर्ड गठित

युवा सहकार टीम

19 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड में एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी भी बने सदस्य

इफको, कृभको, नैफेड और एनसीसीएफ के अध्यक्ष रोटेशन आधार पर सदस्य के रूप में करेंगे काम

लगता है देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द काम करना शुरू कर देगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाना प्रारंभ कर दिया है। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) में नवगठित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त करने के बाद अब मंत्रालय ने इसके पहले गवर्निंग बोर्ड का भी गठन कर दिया है। 19 सदस्यीय इस बोर्ड में सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज श्री दिलीप संघाणी और श्री सतीश मराठे को भी नामित किया गया है। देश में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के कदम के रूप में आजादी के बाद पहली बार सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है।

गवर्निंग बोर्ड 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025' की धारा 21(2) के तहत गठित हुआ है और यह 27 मई, 2025 से प्रभावी हो गया। इस बोर्ड में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, सहकारी संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। बोर्ड में यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. जेएम व्यास, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण तथा मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिवों को जगह दी गई है। इनके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और नाबार्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सीईओ, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक (वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग) श्री नीरज निगम और यूनिवर्सिटी के फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार (सदस्य सचिव) को भी बोर्ड में रखा गया है।

बोर्ड में शामिल उपरोक्त सभी नाम यूनिवर्सिटी के कार्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार के इरादे काफी वृहद हैं। सरकार चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश में सहकारिता को लेकर पेशेवर नजरिया विकसित हो और कॉर्पोरेट सेक्टर की भांति सहकारी समितियों के कामकाज का संचालन भी पेशेवराना अंदाज में हो। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड के नामित सदस्यों के रूप में चार ऐसे नामों का चयन किया है जिन्हें देश के सहकारिता क्षेत्र का दिग्गज माना जाता है। इनमें एनसीयूआई और इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश मराठे, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की एमडी और सीईओ श्रीमती आरती पाटिल और मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट जीना पोटसांगबम का नाम शुमार है। सहकारिता क्षेत्र के इन दिग्गजों की विशेषज्ञता से जमीनी अनुभव और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी। साथ ही, महिला नेतृत्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को भी बल मिलेगा। श्री संघाणी और श्री मराठे का राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जबकि सहकार भारती के संस्थापक सदस्य श्री मराठे के आरबीआई के वित्तीय प्रशासन के अनुभव से बोर्ड के संचालन में जमीनी स्तर की गहराई और नियामकीय अंतर्दृष्टि में मदद मिलेगी।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण को यूनिवर्सिटी की नीतियों में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश, असम, केरल और गुजरात के सहकारिता विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को रोटेशन आधार पर नामित किया गया है। देश की प्रमुख सहकारी संस्थाओं इफको, कृभको, नैफेड और एनसीसीएफ के अध्यक्ष भी रोटेशन के आधार पर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करेंगे। इस रोटेशनल मॉडल का उद्देश्य विविध विशेषज्ञता से समृद्ध एक गतिशील नीति ढांचा प्रदान करना है। सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा। ■

पैक्स का कारोबारी विस्तार बढ़ रहा ग्रामीण रोजगार

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए दो दर्जन से अधिक व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़ा गया

पैक्स के सीएससी, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, राशन की दुकानें आदि खोलने से गांवों में बढ़े रोजगार के अवसर

लिक्विडेशन में गई पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए आएगी नई नीतिः अमित शाह

युवा सहकार टीम

सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारिता की बुनियाद मानी जाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में व्यापक सुधार किया जा रहा है। इसके तहत पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने सहित उसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए उन्हें दो दर्जन से अधिक कारोबारी गतिविधियों से जोड़ दिया गया है। इनमें कॉमन सर्विस सेंटर चलाने, जन औषधि और किसान समृद्धि केंद्र खोलने, उचित मूल्य की राशन दुकानें और अनाज खरीद केंद्र खोलने, पेट्रोल पंप और एलपीजी वितरण केंद्र खोलने, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने और उनका संचालन करने जैसी व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। पैक्स द्वारा इन कारोबारी गतिविधियों को शुरू किए जाने से गांव में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलने लगा है। इसके अलावा, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने निष्क्रिय पैक्स में भी जान फूंकने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार एक नई नीति लाने की तैयारी भी कर रही है। ये पैक्स जब सक्रिय हो जाएंगे तो ये भी ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में मददगार होंगे।

सीएससी से युवाओं को रोजगार

पैक्स का कारोबारी दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने मॉडल बायलॉज में बदलाव किया जिसे देश के सभी राज्यों ने लागू कर दिया है। इनका कारोबारी दायरा बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के कारगर प्रयास के नतीजे अब स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में पैक्स (नए बने पैक्स को छोड़कर) की संख्या करीब 1.05 लाख है। इनमें से करीब 35 हजार पैक्स निष्क्रिय हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब तक पैक्स ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोलने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। देशभर में 44,116 पैक्स इस समय सीएससी के रूप में काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र बनवाने, बैंकिंग गतिविधियों सहित 300 तरह की सेवाएं ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही मिल रही हैं। इन केंद्रों को चलाने के लिए स्थानीय युवाओं को ही चुना जाता है जिससे उनके लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। ये सीएससी गांवों में फोटोकॉपी, प्रिंटिंग आदि की दुकान खोलने जैसे अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बना रहे हैं।

पीएम किसान समृद्धि केंद्र से मिली सहूलियत

इसी तरह, 36,689 पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया है। ये केंद्र किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक का वितरण करने के साथ-साथ किसानों को सलाह भी दे रहे हैं। जहां ये केंद्र खुले हैं वहां के किसानों को अब कृषि इनपुट के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है और न ही लंबी-लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। देशभर में इस समय 22,330 पैक्स उचित मूल्य की राशन दुकानों के रूप में और 19,349 पैक्स अनाज खरीद केंद्र के रूप में काम करने लगे हैं। जबकि, 2,758 पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 799 पैक्स को ड्रग लाइसेंस मिल चुका है और ये जन औषधि केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं ग्रामीणों को देने को पूरी तरह से तैयार हैं। 394 पैक्स ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन दिया है जिनमें से 44 पैक्स का चुनाव हो चुका है और बाकी की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। इसी तरह, 117 ऐसे पैक्स जो पेट्रोल-डीजल के थोक विक्रेता थे, उन्होंने खुद को खुदरा पेट्रोल पंप के रूप में तब्दील करने का आवेदन दिया। इनमें से 55 पैक्स अपने थोक बिक्री केंद्र को खुदरा बिक्री केंद्र के रूप में तब्दील कर पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री करने लगे हैं।

अन्न भंडारण से पैक्स होंगे मजबूत

गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी पैक्स को सौंपी गई है। पानी समिति के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे 822 पैक्स की पहचान की गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और सिक्किम के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है। गुजरात के 58 और मध्य प्रदेश के 26 पैक्स ने पानी समिति के रूप में काम शुरू कर दिया है। इनके अलावा भी पैक्स अन्य कारोबारी गतिविधियों को तेजी से अपनाने

पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया है। ये केंद्र किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक का वितरण करने के साथ-साथ किसानों को सलाह भी दे रहे हैं। जहां ये केंद्र खुले हैं वहां के किसानों को अब कृषि इनपुट के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है और न ही लंबी-लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है।

कवर स्टोरी

पैक्स से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां

- बीज, फर्टिलाइजर और कीटनाशक वितरण
- रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल डीलरशिप
- कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र
- खाद्यान्न खरीद, भंडारण (गोदाम व कोल्ड स्टोरेज) और कृषि उत्पादों की पैकेजिंग
- उचित मूल्य की राशन दुकानें
- मत्स्य पालन, डेयरी और पॉल्ट्री उद्योग
- फार्म मशीनरी कस्टम हायर सेंटर
- बागवानी उत्पादों की खेती
- रेशम उत्पादन
- मधुमक्खी, भेड़, बकरी व सूअर पालन
- सामुदायिक सेवा केंद्र, ब्रांडिंग और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियां
- बीमा सुविधा, बैंक मित्र व व्यावसायिक प्रतिनिधि
- हर घर नल से जल सेवा (जल जीवन मिशन)
- गोबर गैस
- बिजली बिल वितरण और कलेक्शन सेंटर
- लॉकर सुविधा

में जुटे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने और उन्हें संचालित करने का भी जिम्मा पैक्स को दिया गया है। इस योजना के तहत देशभर के पैक्स 7 करोड़ टन भंडारण क्षमता का निर्माण करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में करीब 8,000 टन भंडारण की क्षमता हासिल कर ली गई है, जबकि 500 पैक्स में गोदाम निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में है। पैक्स के कारोबारी विस्तार की वजह से गांवों में अब कृषि कार्यों के अलावा पहले से ज्यादा रोजगार के विकल्प बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे पैक्स का कारोबारी विस्तार होता जाएगा, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में मदद मिलती जाएगी।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, 15 फरवरी, 2023 से लेकर 25 अप्रैल, 2025 तक कुल 19,619 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक (पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन) समितियां बनाई जा चुकी हैं।

बदल रही गांवों की तस्वीर

सहकारिता से सबको जोड़ने और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होंगे तब तक सहकारी ढांचा मजबूत नहीं हो सकता है। 'सहकार से समृद्धि' के जरिये ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2029 तक देश की हर उस पंचायत में पैक्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है जहां अभी पैक्स नहीं है। इसके अंतर्गत पांच वर्ष में 2 लाख नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां बनाई जानी हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, 15 फरवरी, 2023 से लेकर 25 अप्रैल, 2025 तक कुल 19,619 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक (पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन) समितियां बनाई जा चुकी हैं। इन एमपैक्स में पैक्स, लैम्प्स (लॉन्ग एरिया मल्टी परपज सोसाइटी) और एफएसएस (फारमर्स सर्विस सोसाइटी) शामिल हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, देश में इस समय कुल 8,43,099 सहकारी समितियां हैं। इनमें से प्राथमिक समितियां 8,39,244 हैं जिनमें सक्रिय समितियों की संख्या 6,44,608 हैं। 1,48,329 सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं और 46,307 समितियां लिक्विडेशन में हैं।

पैक्स से अपेक्स तक ढांचागत सुधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने 'पैक्स से अपेक्स' तक ढांचागत सुधार का जो बिगुल फूंका है, उसकी वजह से भारतीय सहकारिता आंदोलन की गति तेज हो गई है। सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से 60 से अधिक अहम पहल की गई हैं। ग्रामीण स्तर पर सक्रिय पैक्स के कामकाज को पारदर्शी और कारगर बनाने के लिए मॉडल बायलॉज तैयार कर राज्यों को भेजा, जिसे सभी राज्यों ने अपना लिया। इसके साथ ही पैक्स के विकास के सारे रास्ते खुल गए। पैक्स को आधुनिक बनाने के लिए सभी सक्रिय पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,516 करोड़ रुपए है जिसका 60 प्रतिशत (1528 करोड़ रुपए) हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 30 प्रतिशत (736 करोड़ रुपए) राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों की हिस्सेदारी होगी। बाकी 10 प्रतिशत (252 करोड़ रुपए) का खर्च नाबार्ड उठाएगा। नाबार्ड ही इस परियोजना की नोडल एजेंसी है।

47 हजार पैक्स हुए ऑनबोर्ड

परियोजना के तहत 67,930 पैक्स के कंप्यूटरीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 46,920 पैक्स नाबार्ड के कॉमन सॉफ्टवेयर से जुड़कर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र (9,906) के पैक्स की है। इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात के पैक्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं। बाकी पैक्स का कंप्यूटरीकरण अपने अंतिम चरण में है। आज देश के कई राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक कंप्यूटर नेटवर्क के कारण नाबार्ड से जुड़ गए हैं। सरकार ने पैक्स के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो किसानों के लिए उनकी भाषा में बैंक खाता खोलने का काम करेगा। देशभर में कंप्यूटरीकृत पैक्स हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तमिल और असमिया समेत भारत की 11 मुख्य भाषाओं में काम कर रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था से सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आई है।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण और इंटरनेट से जुड़ जाने से उसके सारे कामकाज ऑनलाइन होने लगे हैं। इससे पैक्स के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में मदद मिल रही है। ऑनलाइन हो जाने और नाबार्ड के एकल सॉफ्टवेयर से जुड़ जाने के बाद कई तरह की अन्य सेवाएं पैक्स से सीधे जुड़ गई हैं, जिससे पैक्स के कारोबार का दायरा बढ़ रहा है और सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में कई तरह के सुधार हो रहे हैं। नाबार्ड में पैक्स की डिजिटल पहुंच हो गई है और पैक्स के वित्तीय लेनदेन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभव हो गई है। सहकारिता की निचली इकाई से लेकर शीर्ष इकाइयां तक एक दूसरे से परस्पर जुड़ रही हैं जिससे सहकारी समितियों के सदस्यों को सीधा लाभ मिलने लगा है।

मॉडल बायलॉज से बढ़ी पारदर्शिता

पैक्स की मजबूती के लिए प्रबंधन संबंधी भी सुधार किए गए हैं। मॉडल बायलॉज के माध्यम से पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आने लगी है। इसमें सदस्यों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इनके बोर्ड में महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। पैक्स के कार्यों

सरकार ने पैक्स के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो किसानों के लिए उनकी भाषा में बैंक खाता खोलने का काम करेगा। देशभर में कंप्यूटरीकृत पैक्स हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तमिल और असमिया समेत भारत की 11 मुख्य भाषाओं में काम कर रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था से सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आई है।

1.05

लाख पैक्स पहले से हैं पंजीकृत

67

हजार पैक्स का किया जा रहा कंप्यूटरीकरण

47

हजार पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा, हुए ऑनबोर्ड

2,758

पैक्स को पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मिली मंजूरी

सरकार जल्द ही लिक्विडेशन में गई पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए नीति लेकर आने वाली है। निष्क्रिय पैक्स में सबसे पहले उनकी पहचान की जाएगी जो चार-पांच साल से निष्क्रिय हैं और उन्हें सक्रिय किए जाने की संभावना मौजूद है। इसके लिए उनकी प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर कर उन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा।

को प्रभावी बनाने के लिए इसमें पेशेवरों को रखने की छूट दी गई है। सहकारिता का लाभ ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पैक्स में भूमिहीन किसान, खेतिहर श्रमिक प्रतिनिधि, पशुपालक, डेयरी किसान, मत्स्य पालक को सदस्य बनाया जा सकता है। पैक्स में किसी को सदस्यता देने से मना नहीं किया जा सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के सदस्यों को सदस्यता देने के प्रावधान को भी सरल बना दिया गया है।

केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री श्री अमित शाह का कहना है, 'पैक्स को सशक्त करने और उसके आर्थिक उन्नयन से ही सहकारी आंदोलन को गति मिलेगी। मॉडल बायलॉज लागू हो जाने से पैक्स के कामकाज का दायरा बढ़ा जो उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा।' सरकार की इस पहल से राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स के बायलॉज में एकरूपता आ गई है, जिससे केंद्र, राज्य, जिला व ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाली सहकारी संस्थाओं को सहूलियत हो रही है।

मॉडल बायलॉज लागू होने से पैक्स को मल्टी परपज बनाने का विकल्प मिल गया है। इससे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। मॉडल बायलॉज को लागू करने से पैक्स को विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के अनुसार, पैक्स की सूची में तकरीबन 80 ऐसे क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिनमें पैक्स अपना कामकाज बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार का उद्देश्य पैक्स को मल्टी परपज बनाकर लाभ कमाने वाली समिति बनाना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी हैं और उनका रुझान सहकारिता की ओर होने लगा है।

बीमार पैक्स की सेहत सुधारने पर भी जोर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार जल्द ही लिक्विडेशन में गई पैक्स के निपटारे और नए पैक्स के लिए नीति लेकर आने वाली है। निष्क्रिय पैक्स में सबसे पहले उनकी पहचान की जाएगी जो चार-पांच साल से निष्क्रिय हैं और उन्हें सक्रिय किए जाने की संभावना मौजूद है। इसके लिए उनकी प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर कर उन्हें फिर से सक्रिय किया जाएगा। दूसरा, ऐसे पैक्स जो 10-20 साल से निष्क्रिय हैं और लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझे हैं, उनके लिए कानूनी सुधार की संभावना तलाशी जा रही है ताकि इसके माध्यम से उनका पंजीकरण रद्द कर उन पंचायतों में नई पैक्स का गठन किया जा सके। चूंकि पैक्स राज्यों का विषय है और ये उन्हीं के कानून से संचालित होते हैं जिनमें एकरूपता नहीं होने से कई तरह की चुनौतियां पेश आती हैं। कई राज्यों में कानूनी सुधार न होने से पैक्स या तो निष्क्रिय हैं अथवा पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए कानूनी सुधार की जिम्मेदारी राज्यों की होगी।

राज्यों की सहमति से पैक्स की प्रक्रियागत खामियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय दिशा-निर्देश तैयार करेगा और राज्यों को एडवाइजरी भेजेगा। उस एडवाइजरी पर अमल कर राज्य कानून में सुधार करेंगे और उसके माध्यम से निष्क्रिय पैक्स को सक्रिय बनाने में मदद मिलेगी।

पैक्स के कई रूप

सहकारी आंदोलन की पहली कड़ी पैक्स की परिकल्पना बहुत पहले ही भारत में कर ली गई थी। असम व छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों और दूर-दूर बसे गांवों को जोड़कर बनाए गए पैक्स को लॉन्ग एरिया मल्टी परपज सोसायटी (लैंप्स) के नाम से जाना जाता है। जबकि कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में फारमर्स सर्विस सोसायटी (एफएसएस) के नाम से भी सहकारी समितियां कार्य करती हैं। देश में सौ साल पुराने पैक्स भी हैं। स्थानीय स्तर पर अल्पकालिक कार्य के लिए इस तरह की समितियां बनी। इसके तहत समिति से सदस्यों को खेती की जरूरतें, शादी, बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य छोटे बड़े कार्यों के लिए आसानी से ऋण मिल जाता है। बैंक न होने के बावजूद पैक्स अपने सदस्यों की जरूरतों को बैंक जैसी सेवाएं देती हैं। सहकारी समिति में सदस्यों के बचत वाला धन एक दूसरे की जरूरतों के लिए जमा होता है। वही इसकी पूंजी होती है, जिससे सदस्यों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। दरअसल, सभी पैक्स जिला सेंट्रल सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के सदस्य होते हैं। पैक्स यहां से ऋण लेकर भी अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जबकि डीसीसीबी लाइसेंसयुक्त बैंक हैं, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से राज्य सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकारें तीन स्तरीय सहकारी संस्थाओं की प्रशासक हैं जो राज्यों के सहकारी कानून से संचालित होते हैं। नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को रिफाइनेंस और सपोर्ट करता है। कंप्यूटरीकरण हो जाने के बाद पैक्स अपने डीसीसीबी और राज्य सरकारी बैंकों के साथ सीधे जुड़ गए हैं। ■

सहकारी आंदोलन की पहली कड़ी पैक्स की परिकल्पना बहुत पहले ही भारत में कर ली गई थी। असम व छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों और दूर-दूर बसे गांवों को जोड़कर बनाए गए पैक्स को लॉन्ग एरिया मल्टी परपज सोसायटी (लैंप्स) के नाम से जाना जाता है। जबकि कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में फारमर्स सर्विस सोसायटी (एफएसएस) के नाम से भी सहकारी समितियां कार्य करती हैं।

अन्न भंडारण योजना से जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा पैक्स

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा की

योजना में राज्यों को अधिक से अधिक पैक्स को शामिल करने और राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशनों को भी इससे जोड़ने का निर्देश

एफसीआई, एनसीसीएफ, नैफेड और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को भी पैक्स को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के दिए निर्देश

युवा सहकार टीम

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पैक्स की आमदनी और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने में मददगार साबित होने वाली है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सहकारिता क्षेत्र को दी गई है जिसके तहत प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) अनाज भंडारण के लिए गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस योजना की समीक्षा के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को अपने स्तर पर अधिक से अधिक पैक्स को इस योजना में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशनों को भी इससे जोड़ा जाए ताकि एक संपूर्ण सहकारी आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने अन्न भंडारण योजना में पैक्स की व्यापक भागीदारी पर बल देते हुए बैठक में कहा कि यह जरूरी है कि पैक्स को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि उसकी वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बैठक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), एनसीसीएफ, नैफेड और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को पैक्स को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने की दिशा में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना एक बड़ा कदम है। देश में आर्थिक प्रगति को मापने के दो प्रमुख मापदंड हैं- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और रोजगार सृजन। अन्न भंडारण योजना इन दोनों पहलुओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, जिसका उद्देश्य पैक्स की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। बैठक में श्री शाह ने कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत ऋण अवधि के विस्तार से पैक्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

इस बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोल के अलावा सहकारिता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, एफसीआई, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहित अन्य संगठनों के अधिकारी उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने सभी संगठनों से समन्वय के साथ योजना को समयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से लागू करने का आह्वान किया ताकि यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर साबित हो। ■

डेयरी क्षेत्र में बनेंगी तीन नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी

सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी विषय पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सहकारी डेयरी क्षेत्र में सतत विकास और सर्कुलर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर

दुग्ध संघों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा डेयरी संयंत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता

युवा सहकार टीम

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार का संकल्प है। सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल मंत्र है। सहकारी डेयरी क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। इसे और आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी डेयरी क्षेत्र के लिए तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी' विषय पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला किया गया।

पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान पर काम करेगी। दूसरी, गोबर प्रबंधन के मॉडल विकसित करेगी और तीसरी सहकारी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्कुलर उपयोग को बढ़ावा देगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा, 'जब हम श्वेत क्रांति 2.0 की ओर अग्रसर हैं, तो हमारा लक्ष्य केवल डेयरी सहकारिता का विस्तार करना और उन्हें कुशल एवं प्रभावी बनाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि डेयरी के एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए जो टिकाऊ हो और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता हो। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एकीकृत सहकारिता नेटवर्क का सृजन करना होगा

नई समितियों के लाभ

- पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान को देगी बढ़ावा
- दूसरी समिति गोबर प्रबंधन मॉडल को करेगी विकसित
- तीसरी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्कुलर उपयोग को बढ़ाएगी

दुग्ध संघों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा डेयरी संयंत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही, वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। ये सभी प्रयास न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि डेयरी क्षेत्र को अधिक सतत एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। सहकारी डेयरी समितियां दुग्ध क्षेत्र में दूध उत्पादन और विपणन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

ताकि अधिकांश कार्य पारस्परिक सहयोग और सहकारिताओं के बीच में ही हो।'

बैठक में शाह ने इस बात पर विशेष बल दिया कि दुग्ध संघों एवं सहकारी समितियों को सशक्त बनाने तथा डेयरी संयंत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही, वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाया जाए। ये सभी प्रयास न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेंगे, बल्कि डेयरी क्षेत्र को अधिक सतत एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। सहकारी डेयरी समितियां दुग्ध क्षेत्र में दूध उत्पादन और विपणन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये समितियां छोटे किसानों को स्थिर बाजार, ऋण सुविधा, पशु चिकित्सा और प्रजनन जैसी सेवाएं प्रदान कर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त भी बना रही हैं।

अमित शाह ने कहा कि हमें मिलकर 'सस्टेनेबिलिटी से सर्कुलरिटी' तक का सफर तय करना है जो बहुआयामी होगा। जो कार्य आज निजी क्षेत्र कर रहे है वह कार्य किसानों की अपनी सहकारी संस्था करेगी। इसमें तकनीकी सेवाएं, पशु आहार, कृत्रिम गर्भाधान, पशु रोग नियंत्रण, गोबर प्रबंधन तथा डेयरी और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में संकलन से लेकर प्रोसेसिंग तक की गतिविधियां शामिल हैं। डेयरी क्षेत्र में अमूल जैसे सफल सहकारी मॉडल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर न केवल डेयरी क्षेत्र में इस सफलता को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि ग्राम स्तरीय सहकारी समितियों को अन्य गतिविधियों से भी जोड़कर उन्हें विस्तारित और मजबूत कर रहा है। ये सभी प्रयास प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को समेकित रूप से हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्वेत क्रांति 2.0 को सफल बनाने के लिए सहकारिता और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय सभी हितधारकों को एक साथ लाया है। इससे अब नीति निर्माण, वित्त पोषण से लेकर ग्राम स्तरीय सहकारिता के गठन और उन्हें बहुउद्देशीय बनाने का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। एनडीडीबी द्वारा विकसित बायोगैस और गोबर प्रबंधन कार्यक्रम का पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। श्वेत क्रांति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। देश के कुल दूध उत्पादन में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी इस समय करीब 14 प्रतिशत है जिसे बढ़ाकर अगले पांच वर्ष में 22-23 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र के उन्नयन के लिए कार्य कर रही राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), एनडीडीबी और नाबार्ड की सराहना करते हुए कहा कि इनके परस्परिक सहयोग से निश्चित रूप से सहकारिता को बल मिलेगा और किसान केंद्रित योजनाओं को पूरे भारत में लागू किया जा सकेगा। ■

सहकारिता से सशक्त हो रहे बिहार के बागवान

युवा सहकार टीम

बिहार की सहकारी क्रांति की गूंज विलायत में भी सुनी जा रही है। राज्य में सहकारिता की अलख अब नए मुकाम पर पहुंचने लगी है। सहकारिता के माध्यम से बिहार के किसानों की उपज अब दुनिया के कई देशों में पहुंच रही है। प्रायोगिक तौर पर यहां की उपज का निर्यात किया गया जिसे वैश्विक मंच पर बहुत सराहा गया है। इससे उत्साहित राज्य के किसानों द्वारा वैश्विक मांग के आधार पर खेती की जा रही है। बिहार के परवल, करेला, बैगन, कटहल और केला के साथ स्वादिष्ट जदार्लु आम भी विश्व बाजार में धूम मचा रहा है। पहली खेप में पहुंची सब्जियां और फलों को उपभोक्ताओं ने हाथोंहाथ लिया है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता में सहकार की भावना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सहकारिता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राज्य सरकार के मुताबिक विदेशों से सब्जियों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले महीने बिहार से सब्जियों और फलों की खेप दुबई के बाजार में भेजी गई है। इनमें 10 किस्म की फल और सब्जियां शामिल थी। विदेशी उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए फल और सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल में सड़क के रास्ते भारी मात्रा में फल और सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है। सिंगापुर की मंडियों से भी आयात मांग आई है, जिसके लिए यहां के निर्यातकों ने वहां के लोगों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया है।

बिहार के कृषि उत्पादों का प्रत्येक सप्ताह 45 टन निर्यात का ट्रायल चल रहा है। इसी के मद्देनजर पूरे राज्य में कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला तैयार की जा रही है, जिससे राज्य के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। घरेलू बाजारों में यहां के उत्पादों की मांग के मद्देनजर हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड ने वैशाली जिले के टमाटर उत्पादक किसानों से खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों से कांट्रैक्ट भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का सुनिश्चित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य में जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें राज्य के किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें विश्व बाजार से निकल रही मांग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान उन्हें बताया जा रहा है कि सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादित फल और सब्जियों का निर्यात शुरू हो गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा किसान हिस्सा ले सकते हैं। निर्यात की पहली खेप में बिहार से 1500 किलोग्राम सब्जियां और फल दुबई भेजे गए। इसमें परवल, करैला, बैंगन, कटहल, केला और जदार्लु आम समेत कुल 10 प्रकार की कृषि उपज शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, नेपाल से 5000 किलो उपज की मांग प्राप्त हुई है और सिंगापुर से भी मांग आई है। कृषि उत्पादों का निर्यात राज्य के किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रत्येक प्रखंड में 10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में यह योजना 52 प्रखंडों में लागू की जा रही है। ■

बिहार के करेला, परवल, बैगन, कटहल, केला और जदार्लु आम की निर्यात मांग बढ़ी

ट्रायल के आधार पर निर्यात की पहली खेप को विदेशी उपभोक्ताओं ने लिया हाथोहाथ

इंटरव्यू

एनसीसीएफ के प्रयासों से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को हो रहा फायदा

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता सहकारी संगठन है जो उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। लंबे समय से यह संगठन निष्प्रभावी था। उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए वर्तमान सरकार ने इसे प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे न सिर्फ इसका कारोबार बढ़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इस सहकारी संगठन को नई ऊंचाई पर ले जाने में एनसीसीएफ के युवा अध्यक्ष **विशाल सिंह** का बड़ा योगदान है। संगठन के कारोबारी विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने उनसे लंबी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंशः

एनसीसीएफ आज जिस कारोबारी मुकाम पर पहुंचा है उसके पीछे क्या कारण है?

मैं वर्ष 2007 से ही सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। वर्ष 2014 से पहले और उसके बाद देश के सहकारी आंदोलन में जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है, खासकर वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद इसमें काफी मजबूती आई है। मैं सितंबर 2022 में चेयरमैन चुना गया था। उस समय एनसीसीएफ का टर्नओवर सालाना 21-23 सौ करोड़ रुपये के आसपास और टैक्स पूर्व मुनाफा 30-32 करोड़ रुपये रहता था। उसके बाद से पौने तीन साल में एनसीसीएफ का टर्नओवर करीब चार गुना बढ़कर 8,200 करोड़ रुपये और टैक्स पूर्व मुनाफा 230 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। यह मेरे लिए, हमारी संस्था और पूरे स्टाफ के लिए गर्व का विषय है कि एनसीसीएफ का भविष्य उज्ज्वल है। इसे इस स्थिति में पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तत्कालीन खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल का भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे अध्यक्ष बनने के पहले दिन से ही मेरा हाथ पकड़ कर एनसीसीएफ को चलाना सिखाया। आज एनसीसीएफ जहां पर भी है उसमें उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है।

संगठन ने किस क्षेत्र में विशेष पहल की जिससे कारोबारी दायरा बढ़ा?

मैं जब चेयरमैन बना तब एनसीसीएफ अपने सप्लायर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर था। संगठन का कारोबारी विस्तार करने के लिए मैंने नैफेड को आदर्श मानकर उन सभी क्षेत्रों में कारोबार करने का प्रस्ताव तैयार किया जिन क्षेत्रों में नैफेड काम कर रहा है। नैफेड कृषि मंत्रालय के अधीन है और एनसीसीएफ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन। संगठन के तौर पर भले ही दोनों अलग-अलग हैं लेकिन दोनों का काम और सदस्यता आधार बहुत हद तक समान है। मेरा मानना था कि जिस तरह से नैफेड प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (पीएसएफ) के तहत किसानों से खाद्य उत्पादों की खरीद करती है, उसी तरह एनसीसीएफ को भी किसानों से सीधी खरीद कर खाद्य उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहिए। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर एनसीसीएफ को इसकी अनुमति भी दी और प्याज, टमाटर, दलहन, तिलहन आदि फसलों की थोक एवं खुदरा खरीद-बिक्री की नोडल एजेंसी बना दिया। मुझे अब यह बताने में बड़ी खुशी है कि हमारा 8,200 करोड़ रुपये का जो टर्नओवर है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पीएसएस और पीएसएफ खरीदी से आता है।

किसानों से खाद्य उत्पादों की सीधी खरीद कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का बड़ा आधार कैसे तैयार किया गया?

देखिए, आज हम नैफेड की तरह दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की नोडल एजेंसी हैं। हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया। बफर स्टॉक के लिए जितना प्याज नैफेड खरीदती है, उतना एनसीसीएफ भी खरीदती है। जब हमने प्याज खरीद शुरू किया था तो पहले साल में नैफेड से एक लाख टन ज्यादा प्याज खरीद कर उन्हें उपभोक्ता मंडियों तक पहुंचाया जिससे पूरे देश में कीमतों को बहुत हद तक नियंत्रित करने में सफलता मिली। पिछले साल हमने रेलवे की मदद से पहली बार कांदा एक्सप्रेस शुरू की थी। हमने नासिक से देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन के जरिये प्याज की आपूर्ति की। वह एक नया अनुभव था। एनसीसीएफ के आने से सिर्फ नैफेड को ही प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि किसानों को भी इस बात का भरोसा हुआ कि एक संस्था और आ गई है जो किसानों के भले के लिए काम करने को तैयार है। किसी एक संस्था पर अगर किसान निर्भर रहेंगे, तो उनका पूरा भला नहीं हो सकता है। किसानों के पास भी अब विकल्प है। इसी तरह, जब देश के कई शहरों में टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच गई थी, तो एनसीसीएफ ने केंद्रीय भंडार, सफल स्टोर और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा बाजार से काफी कम कीमत पर टमाटर की बिक्री कर कीमतों को नियंत्रित किया जिससे उभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली।

> **एनसीसीएफ के आने से सिर्फ नैफेड को ही प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि किसानों को भी इस बात का भरोसा हुआ कि एक संस्था और आ गई है जो किसानों के भले के लिए काम करने को तैयार है। किसी एक संस्था पर अगर किसान निर्भर रहेंगे, तो उनका पूरा भला नहीं हो सकता है। किसानों के पास भी अब विकल्प है।**

सहकारी क्षेत्र में युवाओं की भारी कमी है। आप युवा हैं, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एनसीसीएफ क्या कर रही है?

'सहकार से समृद्धि' का संकल्प युवाओं के बगैर पूरा होना मुश्किल है। युवाओं को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने के लिए देश में पहली बार त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इससे सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नए-नए कोर्स शुरू होंगे जिससे सहकारी क्षेत्र में युवाओं को करियर बनाने का मौका मिलेगा। उनके लिए इस क्षेत्र में नए-नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को सहकारी क्षेत्र की कार्य पद्धति सिखाने और ट्रेनिंग देने में इस यूनिवर्सिटी की बड़ी भूमिका होने वाली है। अभी एनसीसीटी (राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद) के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, वे उसी तरीके से हैं। सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से इसका दायरा और बढ़ेगा। राज्यों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी कृषि और सहकारिता को धीरे-धीरे शामिल किया जा रहा है। इससे भी युवाओं को सहकारिता से जोड़ने में मदद मिलेगी। सहकारी भावना से प्रेरित युवा जब शिक्षण-प्रशिक्षण समाप्त कर लेंगे तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सहकारी संस्थाएं उन्हें नौकरी में प्राथमिकता देंगी। दूसरा, पैक्स की राजनीति की बात करें, तो वर्तमान में इसमें बहुत जल्दी-जल्दी बदलाव हो रहा है। जैसे, अगर आप सिर्फ बिहार का उदाहरण लें तो वहां करीब आठ हजार पैक्स हैं। पहले इनसे जुड़े लोगों की औसत उम्र 50-55 साल होती थी। मगर जब से पैक्स को मजबूत बनाने के लिए उसकी कारोबारी गतिविधियों का विस्तार किया गया है, इससे नौजवान पीढ़ी जुड़ रही है। एनसीसीएफ भी युवाओं को सहकारिता से जोड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। ■

विशेष आलेख

सहकारिता से संवरेगा युवाओं का भविष्य

अभिषेक सिंह राठौर

महाप्रबंधक
नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

भारत युवाओं का देश है और भारतीय युवाओं में असीम क्षमताएं हैं। जरूरत है उन्हें सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग करने की। युवाओं की इस असीमित क्षमता का इस्तेमाल कर ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। इसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सहकारिता क्षेत्र का प्रभाव देशभर में व्यापक रूप से बढ़ रहा है। खासकर केंद्रीय स्तर पर जब से अलग सहकारिता मंत्रालय बना है, तब से इस क्षेत्र में व्यापक सुधार के कई कदम उठाए गए हैं जिससे भारतीय सहकारिता आंदोलन मजबूत हो रहा है।

सहकारी क्षेत्र के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। युवा भारत में सहकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा अपने नए विचारों, ऊर्जा और कौशल के साथ सहकारिता को एक गतिशील और आधुनिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं, उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं और सहकारी समितियों को सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार सहकारी आंदोलन को निरंतर गति, विस्तार एवं दिशा दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसे इन बातों से समझा जा सकता है।

देश के करोड़ों युवा उच्च बेरोजगारी, बढ़ी हुई सहनशीलता और असुरक्षित काम के साथ-साथ लगातार उच्च कामकाजी गरीबी का गंभीर मिश्रण अनुभव कर रहे हैं। उद्यम का सहकारी रूप युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार करने, उन उद्यमों में नौकरी खोजने का साधन प्रदान करता है जो अक्सर उनके अपने मूल्यों के साथ श्रेणीबद्ध होते हैं और उन उद्यमों के सदस्य-मालिक के रूप में भाग लेते हैं जहां उनकी आवाज सुनी जाती है।

एक अनुमान के अनुसार, देश में 15 से 24 वर्ष की आयु के करीब 18 करोड़ युवा हैं। यह दुनिया में इस उम्र के युवाओं की किसी देश में अब तक की सबसे बड़ी आबादी है। इसी उम्र के युवाओं को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग और व्यावसायिक शिक्षा देने की जरूरत है। देश की कार्यशील आबादी में से करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 200 रुपये से भी कम कमाते हैं। वयस्कों की तुलना में युवाओं में बेरोजगारी की संभावना लगभग तीन गुना अधिक है।

सहकारी समितियां सिद्धांत आधारित उद्यम होती हैं जो लाभ कमाने की बजाय लोगों को अपने व्यवसाय के केंद्र में रखती हैं। इस वजह से वे केवल लाभ कमाने से जुड़े मूल्यों की तुलना में व्यापक मूल्यों का पालन करती हैं- जैसे स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता और एकजुटता। सहकारी उद्यम की लोकतांत्रिक प्रकृति भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, स्वामित्व को व्यापक बनाती है और युवाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।

अनुमान है कि सहकारी समितियां दुनिया भर में 10 करोड़ नौकरियां प्रदान करती हैं। हालांकि, इसमें युवाओं का सटीक अनुपात निर्धारित करना मुश्किल है। सहकारी समितियां स्पष्ट रूप से रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उद्यम का सहकारी मॉडल न केवल वेतनभोगी रोजगार प्रदान करके युवाओं को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन की सुविधा भी प्रदान करता है। यह मॉडल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों और सभी शैक्षणिक और कौशल स्तरों के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इनमें हर साल स्नातक हो रहे ऐसे युवा भी शामिल हैं जिनके पास नौकरी पाने की सीमित संभावनाएं होती हैं।

यदि हम युवाओं को सहकारिता की अवधारणा से उचित रूप से परिचित कराएं तो सहकारिता उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान कर सकती है। जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सहकारी समितियां अक्सर सीमित वित्तीय संसाधनों को ज्ञान के साथ एक उद्यम में लगाने में सक्षम बनाती हैं, जो लगभग हर जरूरत और उत्पादक गतिविधि को पूरा कर सकता है।

सहकारी समितियां सामूहिक आवाज और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के माध्यम से अनौपचारिक रोजगार को औपचारिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं।

वित्तीय सहकारी समितियां, मुख्य रूप से सहकारी ऋण संघ दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी 45 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आर्थिक और वित्तीय संकटों के समय में ये लचीलेपन का एक सिद्ध इतिहास है। वे ऋण सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके सभी प्रकार के व्यवसाय के निर्माण और विकास का समर्थन करते हैं। कई सहकारी समितियों ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को देखते हुए युवा और युवा उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट सेवाएं शुरू की हैं, ताकि उन्हें अपना उद्यम शुरू करने, बनाए रखने और विकसित करने की अनुमति मिल सके और सहकारी एवं व्यवसाय के अन्य रूप मे भी समर्थन मिल सके।

सहकारिता क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में देश में पहली बार सहकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) में स्थापित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी न सिर्फ सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि भारतीय सहकारिता क्षेत्र को भी नई दिशा देने का काम करेगी। सहकार की भावना के साथ यहां से शिक्षित और प्रशिक्षित युवा जब नौकरी के बाजार में या स्वरोजगार के लिए आगे आएंगे तो सहकारी संस्थाएं उन्हें प्राथमिकता देंगी।

सहकारिता युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल संवर्द्धन, लोकतांत्रिक भागीदारी और सामुदायिक योगदान के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो एक टिकाऊ और समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। देश के युवाओं के साथ काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी संस्था होने के नाते एनवाईसीएस इस दिशा में प्रयासरत है एवं युवा सशक्तीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है।

सहकारिता युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल संवर्द्धन, लोकतांत्रिक भागीदारी और सामुदायिक योगदान के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो एक टिकाऊ और समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। देश के युवाओं के साथ काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी संस्था होने के नाते नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) इस दिशा में प्रयासरत है एवं युवा सशक्तीकरण की ओर तेज गति से आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। ■

युवा सशक्तीकरण

नीली क्रांति से युवाओं को मिल रहे अवसर

आधुनिक तकनीक से मछली पालन करने और सजावटी मछली पालन में युवाओं के लिए बेहतर संभावनाएं

मत्स्य पालन क्षेत्र में पैक्स और एफएफपीओ के गठन को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय दे रहा बढ़ावा

दो लाख नए पैक्स बनाने के तहत 11 हजार से ज्यादा मत्स्य सहकारी समितियां बनाने का है लक्ष्य

केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में मछली उत्पादन और निर्यात में दोगुने से ज्यादा की वृद्धि

युवा सहकार टीम

नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र की तस्वीर बदलने की केंद्र सरकार की पहल का असर दिखने लगा है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि मछुआरों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है। साथ ही, इस क्षेत्र में युवाओं को भी नए अवसर मिल रहे हैं। परंपरागत मछली पालन की तुलना में बायोफ्लैक जैसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से मछली पालन करने और सजावटी मछली पालन को अपनी आजिविका के रूप में अपनाने में युवा आगे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसी केंद्रीय योजना की इसमें बड़ी भूमिका है। देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी योगदान देता है। मत्स्य पालन क्षेत्र को सनराइज सेक्टर (उभरता क्षेत्र) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह देश के लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का साधान है, खासकर वंचित और कमजोर समुदायों के लोगों की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदम और उनके असर की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने मछली संसाधनों के बेहतर उपयोग और मछुआरों को सुरक्षा निर्देश देने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। साथ ही, स्मार्ट बंदरगाहों और बाजारों के माध्यम से इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण, पकड़ी गई मछलियों के परिवहन और उसकी मार्केटिंग में ड्रोन के उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में एग्रो टेक की तरह ही मत्स्य पालन क्षेत्र में भी मछली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की कार्य प्रणालियों में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवरों में मत्स्य उत्पादन से न केवल इन जल निकायों की जीविका में सुधार होगा, बल्कि मछुआरों की आजीविका में भी सुधार होगा। आय सृजन के एक अवसर के रूप में सजावटी मछली पालन को भी बढ़ावा देने पर भी उन्होंने जोर दिया।

मत्स्य पालन क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के निर्देश से युवाओं के लिए नए-नए अवसर बनेंगे। खासकर, स्मार्ट बंदरगाहों के संचालन, ड्रोन के उपयोग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में उनके लिए बेहतर संभावनाएं बनेंगी। इससे युवा फिशरीज की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होंगे और इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकेंगे। सजावटी मछली का उत्पादन हाल के वर्षों में युवाओं को काफी प्रेरित कर रहा है क्योंकि इससे अच्छी आमदनी होती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 2024-25 में 9 प्रतिशत से अधिक की क्षेत्रीय वृद्धि दर के साथ कुल (अंतर्देशीय और समुद्री) वार्षिक मछली उत्पादन 195 लाख टन पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 184.02 लाख टन था। वित्त वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन की तुलना में पिछले 10 वर्ष में उत्पादन में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये की तुलना में दोगुने से अधिक की वृद्धि है। केंद्र सरकार ने 2015 से विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपए कर दिया है।

195
लाख टन पर पहुंचा वित्त वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन

60,523.89
करोड़ रुपये मूल्य के समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात 2023-24 में हुआ

95.79
लाख टन उत्पादन हुआ था वित्त वर्ष 2013-14 में

38,572
करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए किया गया

भारत की लंबी समुद्री तटीय जल सीमा और अन्तर्देशीय जल भंडार में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने मत्स्य क्षेत्र सहित डेयरी और कृषि क्षेत्र में दो लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जिसे अगले कुछ वर्षों में पूरा किया जाना है। मछुआरों के जीवन को समृद्ध बनाने में यह पहल काफी अहम साबित हो रही है। इससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। पैक्स मछुआरों को रियायती ऋण और अन्य जरूरी इनपुट सेवाएं देते हैं। इन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड का संरक्षण मिलता है।

चीन और इंडोनेशिया के बाद भारत का दुनिया के बड़े मत्स्य उत्पादकों में तीसरा स्थान है। चीन और इंडोनेशिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। विश्व स्तर

मत्स्य पालन क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के निर्देश से युवाओं के लिए नए-नए अवसर बनेंगे। खासकर, स्मार्ट बंदरगाहों के संचालन, ड्रोन के उपयोग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में उनके लिए बेहतर संभावनाएं बनेंगी। इससे युवा फिशरीज की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होंगे और इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकेंगे। सजावटी मछली का उत्पादन हाल के वर्षों में युवाओं को काफी प्रेरित कर रहा है क्योंकि इससे अच्छी आमदनी होती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

मछली उत्पादन बढ़ाने और युवाओं के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर बनाने में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, मत्स्य उत्पादन के बाद की अवसंरचना और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी कुल परियोजना लागत एवं इकाई लागत का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन और जलीय कृषि बुनियादी ढांचा विकास निधि (एफआईडीएफ) का लक्ष्य समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं तैयार करना है। इस योजना में आइस-प्लांट का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज का विकास, मछली परिवहन और कोल्ड चेन नेटवर्क बुनियादी ढांचे, ब्रूड बैंकों की स्थापना, हैचरी, मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मछली चारा मिलों एवं संयंत्रों का विकास और आधुनिक मछली बाजारों का विकास शामिल है। यह योजना मछली उत्पादन में लगे सीमांत मछुआरों सहित छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, कौशल विकास, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान कर रही, जिससे वे अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वर्ष 2020-21 में 20,050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र, जलाशय पिंजरा संस्कृति, खारे और मीठे पानी की जलीय कृषि, मछुआरों का कल्याण, कटाई के बाद की बुनियादी ढांचा सुविधाएं, समुद्री शैवाल, सजावटी और ठंडे पानी की मत्स्य पालन आदि परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों और मछली पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

चीन और इंडोनेशिया के बाद भारत का दुनिया के बड़े मत्स्य उत्पादकों में तीसरा स्थान है। चीन और इंडोनेशिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर जलीय कृषि उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और यह शीर्ष झींगा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है।

पर जलीय कृषि उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और यह शीर्ष झींगा उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। जबकि मछली और मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान कर रहा है। पंचायत स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियों के गठन से इस क्षेत्र को औपचारिक रूप मिलने लगा है जिससे मछली उत्पादन एवं इसके बाद की गतिविधियों को संगठित तरीके से करने से मछुआरों और मछली पालकों का सशक्तीकरण हुआ है।

प्राथमिक स्तर की ये मत्स्य सहकारी समितियां पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना कोष (एफआईडीएफ), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना (पीएमकेएसएसवाई) आदि योजनाओं का लाभ उठाकर आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में सक्षम हो रही हैं। इनमें बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण, मछली कियोस्क, हैचरी का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज प्राप्त करना आदि शामिल हैं। ये समितियां सदस्यों को ऋण सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही समाज के सबसे हाशिए वाले वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करती हैं और उन्हें मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के बीज एवं चारे की खरीद में भी सहायता करती हैं। इन्हें मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारतीय मत्स्य क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ■

युवाओं में बढ़ रही वित्तीय जागरूकता

युवा सहकार टीम

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों का असर दिखने लगा है। नए क्षेत्रों में वित्तीय बाजार की बढ़ती भागीदारी और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए युवाओं में पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड बनवाने की जागरूकता बढ़ रही है। पिछले सात वर्षों में 30 वर्ष तक की आयु के युवाओं को पैन आवंटन में लगभग 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ज्यादातर वित्तीय लेनदेन के लिए पैन का होना अनिवार्य है। इसका आवंटन आयकर विभाग द्वारा किया जाता है।

आयकर विभाग के अनुसार, जारी किए गए कुल पैन की संख्या वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में बढ़कर लगभग 78.4 करोड़ हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह संख्या 43.5 करोड़ थी जो 80 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। जहां तक पुरुषों की बात है तो 2018-19 में 27.35 करोड़ पुरुषों को पैन आवंटित किए गए जिनकी संख्या 2024-25 में बढ़कर 44.47 करोड़ हो गई। महिलाओं के मामले में यह संख्या 2018-19 के 16.17 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 33.97 करोड़ हो गई। युवाओं (युवक और युवती) के मामले में 20-30 वर्ष की आयु में पैन कार्ड बनवाने में तेजी आई। इस उम्र के 11.61 करोड़ युवाओं के पास 2018-19 में पैन था, जो 2024-25 में बढ़कर 18.39 करोड़ हो गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय जागरूकता में वृद्धि की वजह से इसमें तेजी आई है। खासकर, प्रधानमंत्री जन धन जैसी योजनाओं ने वित्तीय समावेशन के महत्व पर जोर दिया है। बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किए जाने से युवा इसे बनवाने के प्रति प्रोत्साहित हुए हैं। इसके अलावा, माता-पिता अपने बच्चों को भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के तहत उनके लिए पैन कार्ड बनवाने में पहले से अधिक सक्रिय हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति ने वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए बच्चों को तैयार करने में योगदान दिया है।

युवाओं के पैन आवंटन में वृद्धि बढ़ती वित्तीय जागरूकता और तेजी से डिजिटल तकनीक को अपनाने को भी दर्शाती है। यह प्रवृत्ति युवाओं के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जुड़ाव से भी प्रेरित है जहां पैन कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। केवाईसी, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए पैन की आवश्यकता होती है। बढ़ती वित्तीय साक्षरता और बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए माता-पिता द्वारा बनाई जा रही योजना भी इसके प्रमुख कारणों में से एक है। नाबालिगों के बैंक खातों को बड़े खातों में परिवर्तित करने से लेकर बच्चों पर केंद्रित निवेश योजनाओं से मैच्युरिटी फंड निकालने, माता-पिता के निवेश में नाबालिगों को नॉमिनी बनाने तक पैन की आवश्यकता होती है। ■

30 वर्ष तक के युवाओं में पैन आवंटन में सात वर्ष में 69 प्रतिशत की हुई वृद्धि

20-30 वर्ष तक के 18.39 करोड़ युवाओं के पास 2024-25 के अंत में था पैन

कुल पैन आवंटन में भी 80 प्रतिशत की वृद्धि, 43.5 करोड़ से बढ़कर 78.4 करोड़ पर पहुंची संख्या

उत्तराखंड में बनेंगे 1000 स्टार्टअप

5 वर्ष में हर जिले में स्थापित होंगे इन्क्यूबेशन सेंटर जिनके माध्यम से स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

200 करोड़ रुपये के उत्तराखंड वेंचर फंड के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम किया जा रहा विकसित

1,300 स्टार्टअप्स उत्तराखंड में बन चुके हैं जिन्हें भारत सरकार से मिल चुकी है मान्यता

युवा सहकार टीम

स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अगले पांच वर्ष में 1,000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य तय किया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी बनाया है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समुचित विकास करने के लिए धामी सरकार स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहयोग प्रदान कर रही है।

पिछले दिनों देहरादून में आयोजित मुख्य सेवक संवाद के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले राज्यभर से आए लोगों से संवाद किया एवं उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पांच वर्ष में प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना है। इन केंद्रों की मदद से 1,000 स्टार्टअप तैयार किए जाएंगे। राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उद्यमिता संबंधित पाठ्यक्रम भी लागू किए हैं। साथ ही डेडिकेटेड स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया गया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वे स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आएं। राज्य सरकार का मत है कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनें। आज देश में नवाचार के माध्यम से बदलाव लाने वालों को एक उचित मंच दिया जा रहा है। प्रतिभाशाली युवा नवाचार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं।

केंद्र सरकार की नीतियों से भारत स्टार्टअप का वैश्विक हब बनकर उभरा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी केंद्रीय योजनाओं से युवाओं के लिए नए मार्ग खुले हैं। उत्तराखंड भी स्टार्टअप क्षेत्र में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। राज्य में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया गया है और स्टार्टअप नीति 2023 को लागू किया गया है। इसके तहत सीड फंडिंग के लिए 15 लाख रुपये तक का अनुदान एवं प्रारंभिक चरण में 22 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। इन्क्यूबेशन सेंटर को शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ा गया है। सरकार इन सभी के नोडल इन्क्यूबेशन सेंटर के रूप में 60 करोड़ रुपये की लागत से देहरादून स्थित आईटी पार्क में विश्वस्तरीय उत्तराखण्ड इनोवेशन हब की स्थापना कर रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड के 1,300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा शुरू किए गए हैं।

स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में शामिल डिजाइन स्टूडियो की फाउंडर श्रद्धा नेगी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को नई पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। वह स्वयं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही हैं और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक जिला एक उत्पाद में स्थानीय कला, वास्तुकला और शिल्प को शामिल किए जाने का आग्रह किया। इन्टीग्रेटेड मेरीटाइम एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के कुणाल उनियाल ने मुख्यमंत्री से डिजिटल अवसंरचना के लिए नीति बनाने और उसे राज्य स्तरीय नवाचार मिशनों में शामिल करने का आग्रह किया। प्लक्स मोटर्स के विकास शाह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रिक बाइक को विकसित किया है जिसके लिए उन्हें शुरुआत में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

उन्होंने मुख्यमंत्री से नवाचारों को प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ाने तक के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान करने एवं टैक्स को कम करने का आग्रह किया।

पिथौरागढ़ से आई हिमग्रेस ऑर्गेनिक्स की संस्थापक बबीता सिंह ने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में खेती कर किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले लोगों को विशेष रूप से सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा स्टार्टअप शुरू करने वाले स्थान तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एग्रीज्वाय एल.एल.पी. के संस्थापक चंद्रमणी कुमार ने बताया कि वे पहाड़ में संरक्षित खेती के माध्यम से कृषि व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्टार्टअप कर रहे लोगों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उन्नत उत्तराखंड नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। ■

केंद्र सरकार की नीतियों से भारत स्टार्टअप का वैश्विक हब बनकर उभरा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी केंद्रीय योजनाओं से युवाओं के लिए नए मार्ग खुले हैं। उत्तराखंड भी स्टार्टअप क्षेत्र में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। राज्य में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया गया है और स्टार्टअप नीति 2023 को लागू किया गया है। इसके तहत सीड फंडिंग के लिए 15 लाख रुपये तक का अनुदान एवं प्रारंभिक चरण में 22 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है।

शुभमन के बहुत काम आएंगे अनुभवी खिलाड़ी

इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया

ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में रहे हैं काफी कामयाब

आठ साल बाद करुण नायर की टेस्ट टीम में हुई वापसी

सत्येन्द्र पाल सिंह

तकनीकी रूप से दक्ष 25 वर्षीय बल्लेबाज शुभमन गिल की कप्तानी में 20 जून से इंग्लैंड में होने जा रही पांच टेस्ट मैच की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया गया है। इस टीम में गिल व उपकप्तान ऋषभ पंत सहित आठ खिलाड़ी हैं जो वहां इससे पहले भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। टीम में करुण नायर को भी शामिल किया गया है जिन्होंने आठ बरस बाद वापसी की है। अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट में उन्होंने दिसंबर 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक जड़ दिया था। वीरेन्द्र सहवाग के बाद वह देश के दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने यह करिश्मा किया है। 2018 में भी उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चुना गया था लेकिन तब वहां उन्हें एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला था। करुण नायर के लिए इंग्लैंड का यह दौरा अपनी दूसरी टेस्ट पारी में टीम इंडिया में जगह पक्की करने का सुनहरा मौका है। इसी तरह, शुभमन गिल के पास भी भारत को जिताने और कप्तान के रूप में अपनी छाप छोड़ने का मौका होगा। गिल को ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का अनुभव बहुत काम आएगा जो इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में काफी कामयाब रहे हैं।

शुभमन गिल ने इंग्लैंड में तीन अलग-अलग टीमों न्यूजीलैंड (2021), इंग्लैंड (2022) और ऑस्ट्रेलिया (2023) के खिलाफ टेस्ट खेले हैं। तीनों मैचों में उन्होंने कुल 88 रन बनाए और सर्वोच्च स्कोर 28 रन रहा। ऐसे में बतौर कप्तान और बल्लेबाज इंग्लैंड में नम मौसम में सीम और स्विंग के खिलाफ उनका कड़ा इम्तिहान होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद बहुत मुमकिन वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करें। गिल ने अब तक 32 टेस्ट में 5 शतक और 7 अर्द्धशतक के साथ 1893 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 123 रहा है। इस दौरे के लिए चुनी गई टीम में रवींद्र जडेजा सबसे अनुभवी हैं। यह उनका तीसरा इंग्लैंड दौरा है। निचले मध्यक्रम में उनका अनुभव भारत के लिए खासा अहम रहने वाला है। इंग्लैंड में खेलते हुए उन्होंने 12 टेस्ट में 642 रन बनाए हैं और 27 विकेट झटके हैं। उन्होंने कुल 80 टेस्ट में 3,370 रन बनाए हैं और 323 विकेट लिए हैं। इसमें 4 शतक, 22 अर्द्धशतक और तीन बार एक टेस्ट में 10-10 विकेट लेना शामिल है। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 175 रन रहा है।

भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का तुरुप का पत्ता कहा जाता है। बुमराह ने इंग्लैंड में अब तक 9 टेस्ट मैच खेल 35 विकेट चटकाए हैं, जबकि उन्होंने कुल 45 टेस्ट में 205 विकेट लिए हैं। केएल राहुल सीम व स्विंग गेदबाजी के खिलाफ मजबूत बल्लेबाजी तकनीक और अनुभव के लिहाज से भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उम्मीद है कि वह इंग्लैंड में नौजवान यशस्वी जायसवाल के साथ टेस्ट में भारत की पारी का आगाज करेंगे। 2021 की टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज राहुल खासे कामयाब रहे और लॉर्ड्स में 129 रन की पारी खेल मैन ऑफ द मैच रहे। इंग्लैंड में 9 टेस्ट खेल उन्होंने 614 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट के पूरे करियर में उन्होंने 58 टेस्ट में 3257 रन ठोके हैं जिनमें 8 शतक और 17 अर्द्धशतक शामिल हैं।

टेस्ट	तारीख	जगह
पहला	20-24 जून	लीड्स
दूसरा	2-6 जुलाई	बर्मिंघम
तीसरा	10-14 जुलाई	लॉर्ड्स
चौथा	23-27 जुलाई	मैनचेस्टर
पांचवां	31 जुलाई-4 अगस्त	द ओवल

उपकप्तान ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर का आगाज विस्फोटक बल्लेबाज व चुस्त विकेटकीपर के रूप में 2018 के इंग्लैंड दौरे में पांच टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट (नॉटिंघम) में किया था। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक 9 टेस्ट खेलकर 556 रन बनाए हैं, जबकि कुल 43 टेस्ट में उनके 2,948 रन है जिनमें 6 शतक और 15 अर्द्धशतक शामिल हैं। इन मैचों में बतौर विकेटकीपर उन्होंने 149 कैच लपके हैं और 15 स्टंपिंग की है। उनका सर्वाधिक स्कोर 159 रन है।

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 2021 के टेस्ट में भारत की जीत में दोनों पारियों सहित (चार-चार विकेट) कुल आठ विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहली पारी में चार विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड में उन्होंने कुल 23 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। अपने टेस्ट करियर में वह 36 मैच में 100 विकेट ले चुके हैं। इस दौरे में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण का वह अहम हिस्सा रहने वाले हैं। ऑलराउंडर शार्दूल ठाकुर इंग्लैंड में सीम और स्विंग की मददगार पिचों पर मुख्य तेज गेंदबाजों के सहयोगी और आठवें नंबर पर भारत की बल्लेबाजी की अहम कड़ी रहने वाले हैं। इंग्लैंड में 4 टेस्ट में 10 विकेट झटकने वाले ठाकुर ने 173 रन भी बनाए हैं। ■

18 सदस्यीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), केएल राहुल (बल्लेबाज), रवींद्र जडेजा (ऑलराउंडर), यशस्वी जायसवाल (बल्लेबाज), साई सुदर्शन (बल्लेबाज), अभिमन्यु ईश्वरन (बल्लेबाज), करुण नायर (बल्लेबाज), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर बल्लेबाज), नीतीश रेड्डी (ऑलराउंडर), शार्दूल ठाकुर (ऑलराउंडर), वॉशिंगटन सुंदर (ऑफ स्पिनर), जसप्रीत बुमराह (तेज गेंदबाज), मोहम्मद सिराज (तेज गेंदबाज), प्रसिद्ध कृष्णा (तेज गेंदबाज), आकाश दीप (तेज गेंदबाज), अर्शदीप सिंह (तेज गेंदबाज), कुलदीप यादव (लेफ्ट आर्म स्पिनर)।

रेपो रेट में कमी से इकोनॉमी को बूस्टर डोज

आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर 5.5 प्रतिशत किया, लगातार तीन बार में 1 प्रतिशत की हुई कटौती

सभी तरह के कर्ज सस्ते होने से बढ़ेगा निवेश जिससे अर्थव्यवस्था की विकास दर में आएगी तेजी

कंपनियों का निवेश बढ़ने से रोजगार के भी नए अवसर होंगे पैदा, महंगाई भी है काबू में

युवा सहकार टीम

महंगाई दर में कमी, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के रुख के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस साल लगातार तीसरी बार रेपो रेट को घटाकर यह साफ कर दिया है कि अब उसका मकसद इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाना है। पहले केंद्रीय बैंक का फोकस महंगाई को नियंत्रित करने पर ज्यादा था जिसके चलते दो साल तक ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई थी। महंगे कर्ज का असर इकोनॉमी पर भी पड़ा और 2024-25 में भारत की विकास दर घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई, जो 2023-24 में 8.2 प्रतिशत थी। ऐसे में आरबीआई के लिए यह जरूरी भी था कि वह कर्ज की दरों को सस्ता करने की ओर अपना कदम बढ़ाए।

ग्लोबल स्तर पर पहले से छाई अनिश्चितता के बीच ट्रंप टैरिफ ने दुनियाभर के देशों की आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे दौर में आरबीआई का यह कदम इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बूस्टर डोज की तरह है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों को घटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रेपो रेट के आधार पर ही बैंक सभी तरह के कर्ज की ब्याज दरें तय करते हैं। कर्ज सस्ता होगा तो उपभोक्ता मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी और इसके लिए निवेश बढ़ाएंगी, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार बढ़ेंगे तो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और इस पूरे चक्र से अंततः अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी।

पिछले साल बेहतर मानसून के चलते देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन (करीब 35 करोड़ टन) हुआ। इसका असर महंगाई दर पर भी पड़ा और महंगाई का स्तर धीरे-धीरे घटकर चार प्रतिशत के आसपास आ गया जो आम उपभोक्ताओं, सरकार और आरबीआई के लिए राहत भरा है। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल भी मानसून बेहतर रहने और इस दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश (106 प्रतिशत) होने का अनुमान जताया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में समय से एक हफ्ते पहले दस्तक देखकर इसे और पुख्ता कर दिया है। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में ब्याज दर घटाने का फैसला करना आरबीआई के लिए आसान था।

कितना घटा रेपो रेट

आरबीआई ने इसी साल फरवरी से रेपो रेट में कटौती का सिलसिला शुरू किया था। फरवरी और अप्रैल की अपनी मौद्रिक समीक्षा नीति में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को एक-एक चौथाई प्रतिशत घटाया था, जबकि जून की मौद्रिक समीक्षा में आधा प्रतिशत की कमी की गई। इस तरह पांच महीने में रेपो रेट में कुल एक प्रतिशत की कटौती हुई जो कर्ज लेने वालों के लिए बड़ी राहत है। ताजा कटौती के बाद रेपो रेट 6 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत रह गया है। इससे हर तरह के लोन की मासिक किस्त घटने का रास्ता साफ हो गया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस कटौती को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंक कटौती का पूरा फायदा पुराने ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। अभी तक जिन सरकारी बैंकों ने अपने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) में कमी की है उन्होंने आधा प्रतिशत (50 बेसिस प्वाइंट) कटौती की है, जबकि निजी क्षेत्र के एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों ने ब्याज दर सिर्फ 10 प्रतिशत (10 बेसिस प्वाइंट) घटाया है। आरबीआई ने सीआरआर (कैश रिजर्व रेश्यो) को भी 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है। इससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ी है और बैंकों के पास कर्ज देने लायक पूंजी अब पहले से ज्यादा हो गई है। सीआरआर के तहत सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर केंद्रीय बैंक के पास नगदी रखनी होती है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक दिसंबर तक रेपो रेट में एक और कटौती कर सकता है।

हालांकि, आरबीआई ने इस साल ब्याज दर में और कटौती की संभावना पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए साफ कर दिया है कि आगे इसकी संभावना नहीं है। आरबीआई ने अपना रुख अकोमोडेटिव (उदार) से बदलकर न्यूट्रल (तटस्थ) कर दिया है। अप्रैल में वह तटस्थ रहने की जगह अकोमोडेटिव हो गया था, जिससे तभी यह संकेत मिल गया था कि वह दरों में और कटौती करने का इच्छुक है। मगर अब वह फिर से तटस्थ हो गया है, जिसका मतलब यह है कि विकास दर के अपेक्षा से कम हो जाने तक अल्पावधि में ब्याज दरों में और कटौती की कोई संभावना नहीं है। तटस्थ रुख का मतलब यह भी है कि कीमतों में अप्रत्याशित और निरंतर वृद्धि की स्थिति में आरबीआई फिर से दरें बढ़ाने के लिए भी तैयार है।

बैंक का नाम	कटौती	आरएलएलआर
	(बेसिस प्वाइंट में)	(प्रतिशत में)
बैंक ऑफ बड़ौदा	50	8.15
पीएनबी	50	8.35
बैंक ऑफ इंडिया	50	8.35
यूको बैंक	50	8.30
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	50	
इंडियन ओवरसीज बैंक	50	8.35
केनरा बैंक	50	8.25
एचडीएफसी बैंक	10	8.9 (एमसीएलआर)

जीडीपी ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहेगी

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जबकि अच्छे मानसून की उम्मीद के चलते इस वित्तीय वर्ष में महंगाई का अनुमान 4 प्रतिशत से घटाकर 3.7 कर दिया है। इससे पहले मई में जब विकास दर के आंकड़े आए थे, तो उसमें वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही जनवरी-मार्च में इकोनॉमी ग्रोथ 7.4 प्रतिशत रही थी, जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6.5 प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ लगाई है। पिछले वित्त वर्ष के लिए भी रिजर्व बैंक ने 6.5 प्रतिशत विकास का अनुमान जताया था। आरबीआई ने भले ही 2025-26 में विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस तरह से दुनिया में भू-राजनीतिक हालात हैं और उसकी वजह से ग्लोबल अनिश्चितता का दौर लगातार बना हुआ है उसे देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर चालू वित्त वर्ष में सिमट कर 6.3 प्रतिशत रह जाएगी। ■

ग्लोबल स्तर पर पहले से छाई अनिश्चितता के बीच ट्रंप टैरिफ ने दुनियाभर के देशों की आर्थिक मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे दौर में आरबीआई का यह कदम इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बूस्टर डोज की तरह है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों को घटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

एनवाईसीएस की मदद से बने आत्मनिर्भर

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) का यह दृढ़ विश्वास है कि युवाओं को यदि सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले, तो उनका सपना साकार हो सकता है। साकार हुआ सपना एक सकारात्मक सोच का विस्तार करता है जिससे अन्य लोग प्रेरित होते हैं। एनवाईसीएस का प्रमुख वित्तीय सहायता कार्यक्रम अनेक लोगों को आत्मनिर्भर बनने, अपने व्यवसाय स्थापित करने और अपने समुदायों को सशक्त करने का अवसर दे रहा है जिससे उनमें सकारात्मकता का संचार हो रहा है।

एनवाईसीएस की मदद से आत्मनिर्भर हुए लोगों में से ऐसी ही एक प्रेरणादायक यात्रा है गुजरात के पाटन के उपाध्याय कृष्णपाल विजयपाल की, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और दृष्टिकोण के बल पर एक सफल उद्यम की नींव रखी। कपड़े की दुकान खोलना उनका सपना था ताकि लोगों की अच्छे कपड़ों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एनवाईसीएस की पाटन शाखा से संपर्क किया। उनकी लगन और प्रतिबद्धता को पहचानते हुए एनवाईसीएस ने उन्हें दुकान खोलने के लिए 11 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की और धीरे-धीरे उसे एक स्थायी और फलता-फूलता व्यापार बना दिया। आज उनके कपड़े की दुकान न केवल उनकी आजीविका का मुख्य आधार है, बल्कि यह कई और लोगों को रोजगार भी दे रही है।

उपाध्याय कृष्णपाल विजयपाल ने युवा सहकार से कहा, 'यह लोन मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, यह विश्वास और प्रोत्साहन का प्रतीक था। एनवाईसीएस ने सिर्फ मेरे व्यापारिक विचार का समर्थन नहीं किया, बल्कि मुझ पर विश्वास किया। आज मैं हर महीने 50,000 रुपये से अधिक कमा रहा हूं। मुझे गर्व है कि मेरे साथ शुरू से जुड़े कर्मचारी आज भी मेरी टीम का अभिन्न हिस्सा हैं।' उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन का भी एक आदर्श उदाहरण है। एनवाईसीएस का उद्देश्य ही ऐसे व्यक्तियों को सशक्त बनाना है जो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों।

> **पाटन के उपाध्याय कृष्णपाल विजयपाल और प्रदीप कुमार चंदूलाल लोधा के सपने हकीकत में हुए तब्दील**

आकांक्षा से उपलब्धि तक

उपाध्याय कृष्णपाल विजयपाल की तरह ही जन साधारण की आकांक्षाओं को उपलब्धि में बदलने की कहानी प्रदीप कुमार चंदूलाल लोधा की भी। उन्होंने किराना दुकान के अपने सपने को हकीकत में तब्दील करने का साहस दिखाया। अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए उन्होंने एनवाईसीएस की पाटन शाखा से 10 लाख रुपये लोन लिया। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से उन्होंने अपनी किराना दुकान का विस्तार किया, वस्तुओं में विविधता लाने और अपने स्टॉक को भी बढ़ाने का काम किया। इससे दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई।

उन्होंने बताया कि लोन मिलने के बाद मैं दुकान में वस्तुओं की विविधता और स्टॉक बढ़ा सका। इसका सीधा असर मेरे ग्राहकों की संख्या और दुकान के टर्नओवर पर पड़ा। यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि एक नैतिक समर्थन भी था। मैं एनवाईसीएस का दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया। आज मैं आर्थिक रूप से सशक्त हूं। उनकी सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि समय पर मिला सही मार्गदर्शन और सहयोग किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। एनवाईसीएस ऐसे ही सपनों को पंख देने का संकल्प लिए निरंतर प्रयासरत है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से मजबूत समुदायों का निर्माण करना इस युवा सहकारी संस्था की प्रतिबद्धता है।

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING FARMERS TO GROW BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD
Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone:** 011-29243412
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS
Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

Rera No. : UKREP10240000585

GOLDEN OPPORTUNITY TO FULFILL
YOUR DREAM OF OWNING A HOUSE IN THE LAP OF

HIMALAYAS

PEACEFUL & SERENE ENVIRONMENT

IN DEHRADUN

2.5 hours drive, Delhi to Dehradun via upcoming Expressway

आलयम
Homes by MDDA

Only Few
H.I.G 3 BHK Flats
Left

SAMPLE FLAT
REAL TIME
PHOTOGRAPHS

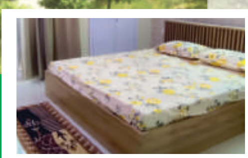
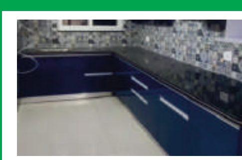
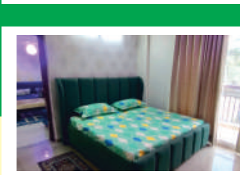
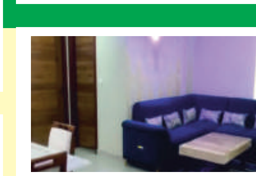
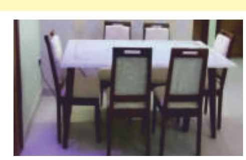

- Mussoorie Dehradun Development Authority brings a residential township in the Lap of nature near Sahastradhara Main Road.
- Pay only 10% at the time of booking, avail 2% additional discount on paying remaining 90% amount in one single time and within one month.
- Additional discount of 1% for females, senior citizens and physically handicapped.

Terms & Conditions applicable.

M.I.G.
2 BHK APPARTMENT

To Get The Location
Please Scan The QR Code

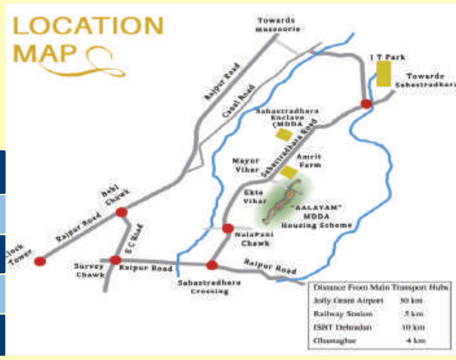

UNIT	SUPER AREA	COVERED AREA	BSP
H.I.G. 3 BHK	1877.83 sq ft	1240.63 sq ft	75.64 Lacs
M.I.G. 2 BHK	1503.40 sq ft	980.88 sq ft	65.85 Lacs
STUDIO APARTMENT	798.18 sq ft	374.02 sq ft	32.29 Lacs
L.IG-C Block	585.82 sq ft	409.42 sq ft	23.29 Lacs

Mussoorie Dehradun Development Authority

Saharanpur Road, Transport Nagar, Dehradun | Ph.: 0135-663150 | Mobile No.: 9012451953
Website : www.mddaonline.in | E mail: info.mdda@mddaonline.in